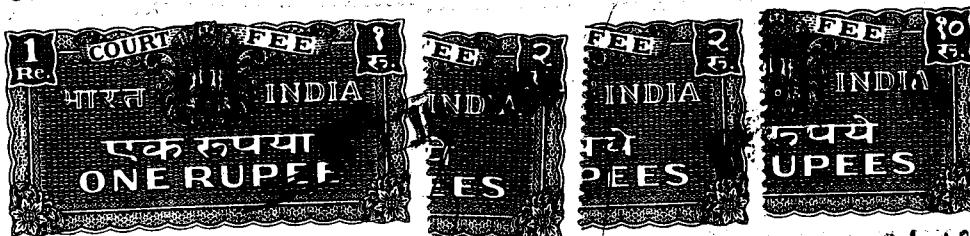


(22)

न्यायालय श्रीमान् राजरव मण्डल म0प्र0 रोकालियर



CFMIS /

R 1233-II/06

राकिने पत्नी रामसिंह खटिक ग्राम कोनिया तह0त्थोरजिलारीपा म0प्र0  
निगरप्रीकरी  
आत्मसंर्किया

बनाम

रामखेलावन तनय जगन्नाथ खटिक ग्राम बलवा तह0त्थोरजिलारीपा म0प्र0

रामखेलावन तनय जगन्नाथ खटिक ग्राम बलवा तह0त्थोरजिलारीपा म0प्र0  
रामखेलावन तनय जगन्नाथ खटिक ग्राम बलवा

रामखेलावन तनय जगन्नाथ खटिक ग्राम बलवा

संभाग रोका प्र० 567 अपील 99-2000 में

पारित आदेश दिनांक 17.4.06 अन्तर्गत धारा

50/- म0प्र0भ०रा0ल01959ई0

गान्धीवर,

प्रकरण के रूपमें तथ्य निम्नानुसार हैं:-

*Signature*

यह कि उत्तराखण्डी रामखेलावन ने ग्राम पंचायत बलवा के प्रजाव कु.4  
नामान्तरण पंजी कु.17 में पारित आदेश दिनांक 10.12.98 के द्वारा  
पूर्ण हत्ता पटाकारी से शौंठ गाँठ कर ग्राम बलवा को आ०न० 263/1 रका  
0.58ए0 को कानूनिक प्रविष्टि करा लिया जिसे अनुचिभागीय अधिकारी  
तथ्योर्थर संघ अपर आयुक्त महोदय रोका संभाग रोका ने लेकार कर लिया।

2:-

यह कि पूर्ण भूमिकाओं द्वारों जो उत्तराखण्डी का कोई वारिश नहीं हैं।

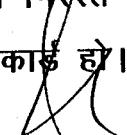
तथा पटाकारी द्वारा कानूनिक प्रविष्टि जबकि द्वारों उस त्रैये जोषित था

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1233—दो / 2006

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ते एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-03-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा मृतक ददोली को पक्षकार बनाकर आदेश पारित कराया है। मृत व्यक्ति को न तो पक्षकार बनाया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अनावेदक के पक्ष में दिनांक 10-12-98 को नामांतरण आदेश पारित किया गया था। इसके बाद अनावेदक भूमिस्वामी के रूप में दखल में है। यदि आवेदक उक्त भूमि ने संबंध में नामांतरण आवेदन किया था तो उसे अनावेदक को पक्षकार बनाकर बनाकर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 109 / 110 का पूर्णरूप से पालन किये बिना त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी को सही पाते हुये अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-4-2006 में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होन से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> 	(एस०एस० अली) सदस्य